बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 4

## प्रवर्तकों पर नरमी

**जेट** एयरवेज अपनी बहुलांश हिस्सेदारी कर्जदाताओं को एक रुपये में बेच रही है। यह बिक्री एक जटिल व्यवस्था के तहत की जा रही है, इस विषय पर आगामी 21 फरवरी को निर्णय लिया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में कर्जदाताओं के एक समूह ने देश की सबसे बड़ी पूर्णकालिक सेवा प्रदान करने वाली इस विमानन कंपनी में 50.1 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए 11.4 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा गत वर्ष प्रस्तुत एक खाके के अनुरूप ही है। यह प्रक्रिया नकारात्मक नेटवर्थ वाली कंपनियों पर लागू होती है और इसे बैंक-लेड प्रोविजनल रिजॉल्युशन प्लान का नाम दिया गया है। इसके लिए प्रवर्तक समूह और एतिहाद के बोर्ड समेत तमाम अंशधारकों की मंजूरी आवश्यक होगी। एतिहाद की जेट में 24 फीसदी हिस्सेदारी है। दिक्कत यह है कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है।

यह अच्छी खबर है कि जेट एयरवेज शायद संभावित संकट से बच जाएगी लेकिन यह बात अहम है कि जेट एयरवेज बची रहे। अगर ऐसा होगा तभी नागरिक उड्डयन क्षेत्र में समुचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो सकेगी। फिलहाल इस क्षेत्र में सस्ती विमानन सेवा इंडिगो का दबदबा है। परंतु इस प्रस्तावित राहत के कुछ अन्य पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहली बात, योजना यह है कि राष्ट्रीय निवेश एवं अधोसंरचना फंड (एनआईआईएफ) जेट के 8,500 करोड़ रुपये के कर्ज को निपटाने में कुछ राशि का सहयोग करेगा। यह अपने आप में एक पहेली है। एनआईआईएफ की स्थापना बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस फंड में निजी निवेशकों और सरकार के बीच साझेदारी है। इसका उद्देश्य है ऐसी बुनियादी परियोजनाओं को निवेश मुहैया कराना जिन्हें फिलहाल निजी पूंजी से नहीं बनाया जा सकता है। बहरहाल, एनआईआईएफ का इस्तेमाल कर जेट एयरवेज को उबारना सही संकेत नहीं है। इससे भविष्य के निजी निवेशकों को यह संकेत मिलेगा कि सरकार इस फंड का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सहज कॉर्पोरेट बचाव के लिए कर सकती है। ऐसे में यह समझना मुश्किल है कि निजी निवेशक फंड पर आगे भरोसा क्यों करेंगे? इसके अलावा ऐसे प्रश्न भी उठेंगे कि बैंकों को किसी ऐसी कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी रखनी चाहिए या नहीं जो नागर विमानन जैसे अत्यंत जोखिम भरे क्षेत्र में काम कर रही हो।

एक सवाल यह भी है कि डेट-इक्विटी वाले इस सौदे में जिसमें स्पेशल राइट का मसला शामिल है, उसमें जेट के संस्थापक और प्रमुख नरेश गोयल को 20-21 फीसदी हिस्सेदारी रखने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। यह उनकी मौजूदा 50 फीसदी की हिस्सेदारी के आधे से भी कम है। सवाल यह है कि आखिर गोयल को राहत पैकेज के बाद भी किसी तरह की हिस्सेदारी क्यों सौंपी जा रही है? अगर बैंकों जैसे कर्जदार बोझ वहन कर रहे हैं तो वित्त जगत के मूलभूत सिद्धांत कहते हैं प्रवर्तक (इस मामले में गोयल) को कोई हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। शेयर का जोखिम, कर्ज के जोखिम से बड़ा है और कर्जदारों का बकाया शेयर धारकों के पहले चुकाया जाना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सौदे में जेट के प्रवर्तक के प्रति काफी नरमी बरती जा रही है और यह मामला किंगफिशर एयरलाइंस के प्रति बैंकों की नरमी की याद दिलाता है। बैंकों ने माल्या के विमानन कंपनी का मालिक रहते हुए भी उसमें काफी पैसा डाला। प्रभावी तौर पर देखा जाए तो बैंक एक निजी विमान कंपनी के लिए जनता के पैसे को दांव पर लगा रहे हैं। जेट के कुल कर्ज में स्टेट बैंक की हिस्सेदारी एक चौथाई है। ऐसे सौदों को रुक जाना चाहिए था, तो अब तक प्रवर्तकों को ऐसी पेशकश क्यों की जा रही है।

बिनय सिन्हा

# सुव्यवस्थित सांख्यिकी तंत्र के अभाव में बिगड़ता खेल

हमें अपनी सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार करना होगा, अन्यथा अपर्याप्त और राजनीतिक नजरिये से तैयार अस्पष्ट आंकड़ों के बीच नीतियां बनाने के लिए हमारी आलोचना होती रहेगी। बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

जॉन मैनार्ड कींस को आमतौर पर वृहद अर्थव्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। उनकी 1936 में प्रकाशित पुस्तक 'द जनरल थिअरी ऑफ एंप्लॉयमेंट, इंट्रेस्ट ऐंड मनी' को इस क्षेत्र में सबसे अहम माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो प्रमुख अवधारणाएं दीं उनमें, समेकित मांग और आपूर्ति, खपत, निवेश और उत्पादन से उसका संबंध, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां आदि सभी शामिल हैं। सन 1930 के दशक की महामंदी के कारण कींस और उनके समकालीन अर्थशास्त्रियों के दिमाग में उत्पादन और रोजगार सबसे अधिक अहमियत रखते थे। वृहद अर्थव्यवस्था के सिद्धांत पर उनके योगदान ने राष्ट्रीय आय के अंकेक्षण जैसे उभरते क्षेत्र को गति दी। कॉलिन क्लार्क, सिमॉन कुज्नेट और रिचर्ड स्टोन जैसे दिग्गज सामने आए। वृहद आर्थिक नीति के समर्थन और उसके व्यवहार को लेकर सिद्धांत और आंकड़े सामने आने लगे।

कई बार मुझे आश्चर्य होता है कि आखिर कैसे दुनिया के औद्योगिक देश सन 1930 के पहले अपनी आर्थिक नीति चला रहे थे। उनके पास वृहद अर्थव्यवस्था के आकलन का कोई ढांचा नहीं था, न ही राष्ट्रीय आय और रोजगार के विश्वसनीय आंकड़े। मौजूदा भारत में भले ही हमारे पास वृहद अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत और वृहद अर्थव्यवस्था की आधारभूत बातें हों लेकिन इनमें इजाफा हो रहा है। हमारे यहां सकल घरेलू उत्पाद समेत आर्थिक मोर्चे पर अधूरे आंकड़े हैं। इनमें रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े भी शामिल हैं। जब आप इस बात को लेकर सुनिश्चित न हों कि आर्थिक वृद्धि में धीमापन आ रहा है या तेजी और रोजगार के हालात कैसे हैं तो ऐसे में राजकोषीय या मौद्रिक नीति निर्माण आसान नहीं है।

जरा हालिया जीडीपी वृद्धि आंकड़ों पर गौर करें। जनवरी 2015 में जब तक 2004-05 के पुराने आधार वर्ष को बदलकर 2011-12 नहीं किया गया था, सब ठीक चल रहा था। आधार वर्ष को बदलने के अलावा आकलन पद्धति और डेटा स्रोत में भी अहम बदलाव किया गया। इससे कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गईं। इसके चलते वर्ष 2013-14 के वृद्धि अनुमान में काफी उछाल आई। यह वही वर्ष था जब हमें एक छोटा भुगतान संतुलन संकट झेलना पड़ा था। उसी वक्त नीतिगत ब्याज दरों में 300 आधार अंकों का इजाफा भी किया गया था। पुराने मानकों से इतर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 2011-12 के पहले के आंकड़ों को दो वर्ष तक नए आधार वर्ष के हिसाब से समायोजित नहीं किया। इस अंतर को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने वास्तविक क्षेत्र की सांख्यिकी संबंधी समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता डॉ. सुदीप्त मुंडले के पास थी और देश के मौजूदा मुख्य आर्थिक सलाहकार उसके सदस्य सचिव बने। समिति ने सन 1994-95 से 2011-12 तक के अपने अनुमान जुलाई 2018 में प्रकाशित किए। यह प्रकाशन 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए किया गया।

वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक के संप्रग के कार्यकाल को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है और इन वर्षों को लेकर भी इन नए अनुमानों में करीब आधा फीसदी का सुधार दर्शाया गया। इस पर विवाद उत्पन्न हो गया। संभवत: इन बैक सीरीज आंकड़ों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही सीएसओ उत्साहित हो गया और उसने नवंबर 2018 में अपनी बैक सीरीज जारी कर दी। इस नई सीरीज ने एनएससी द्वारा जारी अनुमान को प्रति वर्ष दो फीसदी तक पीछे छोड़ दिया।

एक पखवाड़ा पहले मौजूदा 2011-12 आधारित जीडीपी आंकड़ों पर नए सिरे से संदेह उत्पन्न हो गया जब 2016-17 के शुरुआती आंकड़ों के लिए पहले जताई गई 7 फीसदी की दर को संशोधित कर 8.2 फीसदी कर दिया गया। इससे एक नई बहस छिड़ गई कि क्या नोटबंदी वृद्धि दर बढ़ने में सहायक है?

जहां तक रोजगार के आंकड़ों की बात है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने 2017-18 का अपना सर्वेक्षण जून 2018 में पूरा कर लिया। प्रेस में आई खबरों के मुताबिक एनएससी ने दिसंबर के आरंभ में इस रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी लेकिन अभी भी इसका जारी होना शेष है। हाल ही में एनएससी के दो गैर कार्यकारी सदस्यों के इस्तीफे से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। इनमें कार्यवाहक अध्यक्ष भी शामिल थे। रिपोर्ट या जैसा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहते हैं मसौदा रिपोर्ट के कुछ हिस्से दो सप्ताह पहले लीक हो गए। यह रिपोर्ट 2011-12 से रोजगार के आंकड़ों को लेकर निराशाजनक रुझान प्रस्तुत करती है। बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1 फीसदी हो गई। 15 से 29 की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर काफी बढ़ी और ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी 13.6 फीसदी और शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी थी। सभी आयु वर्ग में श्रम शक्ति की भागीदारी में काफी गिरावट आई थी। यह घटकर 23 फीसदी रह गई। युवा महिलाओं में तो यह 16 फीसदी के निराशाजनक स्तर तक पहुंच गई। जाहिर है महिला सशक्तीकरण केवल जुमला बनकर रह गया। संयोग देखिए कि बेरोजगारी में इजाफा और श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट को हाल में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी के आम घरेलू सर्वेक्षण में भी दर्ज किया गया है।

गत सप्ताह नीति आयोग के सीईओ (एनएससी के पूर्व सदस्य) ने इस समाचार पत्र के अंग्रेजी संस्करण में दो हिस्सों में एक आलेख लिखकर विवाद को और बढ़ावा दे दिया। उन्होंने उक्त मसौदा रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा कि यह रिपोर्ट उनके पास नहीं भेजी गई और न ही वह वह एनएससी की इससे संबंधित बैठकों में मौजूद रहे। उन्होंने रोजगार के मोर्चे पर आंशिक रूप से बेहतर अनुमान पेश किए। उनकी आलोचना कमजोर नजर आती है हालांकि पूरा आकलन तभी हो सकेगा जबकि पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाए। देश में रोजगार की स्थितियों को लेकर जानकारी का स्तर कुछ ऐसा है।

यह अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं। हमें तत्काल राष्ट्रीय आय शृंखला की मौजूदा शृंखला के स्रोत और तौर तरीकों की समीक्षा करनी होगी और जरूरी सुधारों को अंजाम देना होगा। हमें सीएसओ की स्वायत्तता बहाल करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इसके पास इन भारी दायित्व के निर्वहन के लिए जरूरी गुणवत्ता और मात्रा का होना आवश्यक है। एनएसएसओ के लिए भी ऐसे ही एजेंडे की आवश्यकता है। इस दौरान रोजगार, श्रम शक्ति के सर्वेक्षणों तथा इनकी रिपोर्ट को खास प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। सांख्यिकी तंत्र को मजबूत बनाने और उनमें सुधार का कोई विकल्प नहीं है। इनको वह पेशेवर स्वायत्तता मिलनी चाहिए जो उन्हें अब तक मिलती आई है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी आलोचना होती है कि हम अपर्याप्त आंकड़ों और राजनीतिक चश्मे से देखी जा रही सूचना के आधार पर नीतियां बनाते हैं।

*(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में प्रस्तुत विचार निजी हैं।)*

# मोदी सरकार में संसाधनों के इस्तेमाल पर उठते सवाल

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

मोदी सरकार का पांच वर्षों में पीएसयू के लिए पूंजी आवंटन यह दर्शाता है कि उसने संभवतया इक्विटी के लिए आवंटित संसाधनों के एक बड़े हिस्से को बरबाद होने दिया। यह सरकार की कड़े फैसले लेने की अक्षमता को भी दर्शाता है

**नरेंद्र** मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) को पूंजी मुहैया कराने में अहम बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पीएसयू के लिए आवंटन में बढ़ोतरी के बावजूद इन सरकार नियंत्रित उद्यमों में आंतरिक संसाधन सृजन तुलनात्मक रूप से कम है और इन पांच वर्षों में सरकार की पीएसयू लाभांश पर निर्भरता में बढ़ोतरी जारी रही।

पीएसयू के साथ सरकार के जुड़ाव का एक अहम संकेतक वह बजट मदद है, जो वह इन उद्यमों को मुहैया कराती है। इस मामले में भी मोदी सरकार ने काफी अधिक बजट सहायता मुहैया कराई, जिसका कुल बजट खर्च में हिस्सा इन पांच वर्षों में दोगुने से अधिक यानी 9 फीसदी से अधिक हो गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी की गहन जांच से पता चलता है कि सरकार नियंत्रित उद्यमों को लेकर मोदी सरकार की नीति में बुनियादी कमजोरी है। सरकार पीएसयू को 90 फीसदी से अधिक बजट सहायता इक्विटी के रूप में देती है। शेष सहायता ऋण के रूप में दी जाती है। मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान इक्विटी के जरिये पीएसयू में 6.26 लाख करोड़ रुपये झोंके जाने का अनुमान है। लेकिन इस राशि में से करीब 94 फीसदी पीएसयू कंपनियों के चार समूहों में गई। इस राशि में से 2.53 लाख करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, 2.07 लाख करोड़ रुपये भारतीय रेलवे, 1.14 लाख करोड़ रुपये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और 17,320 करोड़ रुपये एयर इंडिया को मुहैया कराए गए।

भारतीय रेलवे और एनएचएआई को इक्विटी पूंजी मुहैया कराने को लेकर कोई हो-हल्ला नहीं होना चाहिए। निस्संदेह सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मुहैया कराई गई पूंजी का सदुपयोग होना चाहिए ताकि उससे पर्याप्त प्रतिफल मिले और रेलवे एवं सड़क क्षमता में बढ़ोतरी हो। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार को हमेशा इन दो अहम बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को पर्याप्त संसाधन मुहैया कराने चाहिए।

असल में मोदी सरकार का भारतीय रेलवे में इक्विटी योगदान पांच वर्षों के दौरान मनमोहन सिंह सरकार के दूसरे कार्यकाल 2009-10 से 2013-14 या संप्रग-2 के मुकाबले करीब दोगुना रहा। मोदी सरकार के दौरान एनएचएआई के लिए इक्विटी आवंटन मनमोहन सिंह के पांच वर्षों के मुकाबले करीब डेढ़ गुना अधिक रहा। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इक्विटी आवंटन में भारी बढ़ोतरी को लेकर सवाल उठेंगे। यह 2009-14 के दौरान 45,517 करोड़ रुपये था, जो 2014-19 के दौरान 2.53 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

साफ तौर पर इक्विटी आवंटन में भारी बढ़ोतरी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिक पूंजी पर्याप्तता की जरूरत की वजह से हुई क्योंकि उनकी फंसे कर्जों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्या यह तय करने पर पर्याप्त विचार-विमर्श किया गया कि सरकार नियंत्रित किस कुशल बैंक को ऐसी इक्विटी पूंजी मिलनी चाहिए? या यह पूंजी हर सरकार नियंत्रित बैंक को उनका प्रदर्शन देखे बिना दी गई? यह बड़ी राशि है। क्या सरकार ने केवल कुशल बैंकों पर ध्यान देकर और अकुशल बैंकों को पूर्वनिर्धारित समय सीमा के दौरान अपने परिचालन को समेटने के लिए कहकर इस पैसे का सदुपयोग किया?

इससे भी चिंताजनक मोदी सरकार के पांच साल के कार्यकाल के दौरान एयर इंडिया को इक्विटी का आवंटन है। एयर इंडिया में वर्ष 2014 से 2019 के दौरान करीब 17,320 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है। सरकार ने एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन राजनीतिक विरोध और निजीकरण के गलत तरीके समेत कई वजहों से एयर इंडिया सरकार के गले की फांस बनी हुई है।

अब भी एयर इंडिया केंद्रीय सरकारी खजाने को चपत लगा रही है। असल में मोदी सरकार द्वारा एयर इंडिया के लिए मुहैया कराई गई 17,320 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी संप्रग-2 से अधिक है। संप्रग-2 ने अपने पांच साल के कार्यकाल में एयर इंडिया को 15,200 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी मुहैया कराई थी। रोचक बात यह है कि 2019-20 के अंतरिम बजट में एयर इंडिया के लिए इक्विटी पूंजी का आवंटन नहीं किया गया है। क्या इसका यह मतलब है कि सरकार 2019-20 में एयर इंडिया की रणनीति बिक्री करने में कामयाब रहेगी? इस समय इसके बहुत कम आसार नजर आ रहे हैं। इसलिए पीएसयू में इक्विटी के लिए प्रावधान करना यह दर्शाता है कि अनुमान कम रखा गया है। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इक्विटी आवंटन भी अनुमान से कम है। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की और पूंजी की जरूरत अभी पूरी नहीं हुई है। उम्मीद है कि इन जरूरत से कम अनुमानों को पूर्ण बजट में ठीक किया जाएगा, जो जुलाई 2019 में पेश होने की संभावना है।

लेकिन मोदी सरकार का पांच वर्षों में पीएसयू के लिए पूंजी आवंटन यह दर्शाता है कि उसने संभवतया इक्विटी के लिए आवंटित संसाधनों के एक बड़े हिस्से को बरबाद होने दिया। यह सरकार की कड़े फैसले लेने की अक्षमता को भी दर्शाता है। भले ही ये फैसले निजीकरण से संबंधित हों या सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को अपना परिचालन बंद करने के लिए बाध्य करने से संबंधित हो।

## कानाफूसी

### क्षणिक खुशी

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने का काम सौंपा और उनको क्षेत्र का प्रभारी बनाया तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेता प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि अब प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का दखल न के बराबर होगा क्योंकि उनके पास इसके लिए वक्त ही नहीं होगा। वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि अब लोकसभा चुनाव के पहले होने वाले टिकट वितरण में उनकी चल सकेगी। परंतु उनका यह स्वप्न दिवास्वप्न साबित हुआ। दरअसल इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि न केवल सिंधिया अपनी पारंपरिक गुना-शिवपुरी सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि वह ग्वालियर-चंबल क्षेत्र से भी अपने करीबियों के लिए कुछ सीट मांग सकते हैं। गौरतलब है कि हालिया विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था।

### बदमजा राजनीति

पुदुच्चेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और विपक्षी दलों के निशाने पर रहीं। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का मजाक उड़ाया था। नारायणसामी राज्य के प्रशासन में बेदी के कथित हस्तक्षेप के विरुद्ध धरने पर बैठे थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मीडिया में से किसी ने मुझसे एक रोचक प्रश्न किया कि क्या धरना भी योग है? मैंने कहा हां है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से धरने पर बैठे हैं, आप कौन सा आसन कर रहे हैं और किस तरह की आवाज निकाल रहे हैं। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक कौए की तस्वीर ट्वीट की और लिखा, कौआ आसन। कांग्रेस नेताओं और सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं ने कहा कि यह पोस्ट बेकायदा थी। कुछ लोगों ने बेदी की पुरानी तस्वीर ट्वीट करनी शुरू कर दी जब 2011 में वह अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान धरने पर बैठी थीं।

## आपका पक्ष

### संयंत्रों की स्थापना करेगी बेरोजगारी दूर

आज देश में अच्छे-अच्छे कल-कारखाने सरकार के कठोर नियमों के कारण बंद हो गए हैं या फिर बंदी के कगार पर हैं। खासकर जयपुर में जैसे जयपुर मेटल के अलावा अन्य कारखाने सरकारी नियमों के कारण बंद हो गए हैं। इन कारखानों के पास करोड़ों रुपये मूल्य की काफी जमीन है जिसे सरकार ने उन्हें रियायती दर पर दी थी। ऐसे कारखानों को दोबारा शुरू करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार देश में नए कारखाने खोलने की भी जरूरत है। इन कारखानों में उपयोग होने वाला कच्चा माल उसी क्षेत्र से लिया जाना चाहिए। राजस्थान में लोहे तथा तांबे की खानें हैं जिनका इस्तेमाल कारखानों में किया जा सकता है। राज्य के खेतड़ी में तांबे की खान है जहां से कच्चा माल काफी कम कीमत पर भेजा जाता है। उसी तांबे को उत्पाद बना कर हजारों रुपये में बेचा जाता है। सरकार

को देश में नए कारखाने खोलने के लिए प्रवासी भारतीय को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे देश के अलग-अलग जगहों में नए कारखाने खुल सकते हैं जिससे बेरोजगारी दूर करने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा इससे होने वाली आय से देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा राजस्व घाटा पाटने में मदद मिलेगी। सरकार को इस

**बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए**

दिशा में ठोस नीति बनानी चाहिए जिससे वर्तमान में देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी दूर करने में काफी मदद मिलेगी।

*घेवरचंद गोदीका, जयपुर*

### उज्ज्वला योजना में रिफिलिंग बड़ी बाधा

उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को दिया गया गैस कनेक्शन (सिलिंडर और चूल्हा) न तो मुफ्त है और न ही सिलिंडर पर (मार्च 2018 तक) सब्सिडी मिली है। लाभार्थी को गैस कनेक्शन लेते ही 1,750 रुपये चुकाने पड़ते हैं। सरकार पहले छह सिलिंडर की रिफिलिंग के दौरान करीब 1,740 रुपये प्रति ग्राहक वसूल लेती थी। शायद यही वजह है कि अधिकांश उपभोक्ता दूसरी बार सिलिंडर नहीं भरवाते हैं। करीब 50 फीसदी उपभोक्ता हर दो महीने, 30 फीसदी 3-4 महीने में एक बार सिलिंडर लेते हैं। जब यह योजना असफल होने लगी तो सरकार ने गैस सिलिंडर पर सब्सिडी देने का फैसला किया। सरकार घरों के चूल्हों को गैस से जलाने के लिए प्रयत्नशील है। फिर भी प्रश्न यह है कि गरीबों के घरों में एक बार रिफिलिंग होने वाले गैस सिलिंडर कैसे बार-बार भरे जाएं।

*दीप कुमार, महराजगंज*

### उत्साहित है सरकार

उज्ज्वला योजना का मकसद महिलाओं को किफायती दरों पर गैस कनेक्शन देना है। इस योजना के बाद शुद्ध ईंधन के प्रयोग से महिलाओं में सांस संबंधी बीमारी होने का खतरा कम हुआ है और महिलाएं ज्यादा सशक्त महसूस कर रहीं हैं। पहले की तुलना में महिलाओं का समय भी बचता है और घर के अंदर और बाहर होने वाले वायु प्रदूषण पर भी रोक लगी है। इस योजना के कारगर होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने इस वर्ष के बजट में तीन करोड़ अतिरिक्त गैस कनेक्शन देने के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब इससे और भी महिलाएं लाभान्वित होंगी।

*शुभम दियावार, जबलपुर*

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**